क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन
दंडकारण्य

प्रेस वक्तव्य

दिनांक–30 जनवरी, 2021

किसान बहनों व भाईयों हम आपके साथ हैं!

मोदी सरकार द्वारा लाए गए किसान विरोधी व जन विरोधी तीन कृषि कानूनों के विरोध में 2021 सितंबर से आप जो संघर्ष कर रहे हैं उसका क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन जोरशोर से समर्थन करता है. दिल्ली में, देश के कोणे–कोणे में उफान की तरह उठ रहे आपके संघर्षों का दंडकारण्य की क्रांतिकारी महिलाएं तहेदिल से स्वागत करती हैं. जाहिर है कि ये तीन कानून कृषि और किसानों को पूरी तरह बरबाद करने वाले हैं. उतना ही नहीं देश की 80 फीसदी आम जनता को ये कानून बुरी तरह प्रभावित करने वाले हैं. छोटे व्यापारियों को भी तबाह करने वाले हैं. कृषि जिस पर देश की 60 प्रतिशत आबादी निर्भर है, को तबाह करने वाले किसानों सहित लगभग 80 फीसदी जनता की जिंदगी को बद से बदतर करने वाले इन कानूनों को कार्पोरेट घरानों, बड़े व्यापारियों, जमाखोरियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं. ज्ञात है कि देश के किसानों, कृषि मजदूरों, उपभोक्ताओं में आधी आबादी महिलाओं की ही है. कृषि को तबाह करने वाली हर नीति महिलाओं को और अधिक प्रभावित करती है. आज देश में जारी कृषि संकट के चलते लाखों की तादाद में किसान भाईयों ने आत्महत्या कर ली. इससे महिलाओं की मुश्किलें और बढ़ रही हैं. उन्हें अकेली ही परिवार का भार संभालना पड़ रहा है. कर्ज के बोझ से दब रहे परिवार की मदद के लिए, बाल–बच्चों को पालने के लिए कई महिलाओं को आखिर अपने देह को भी बेचना पड़ रहा है. अपनी बच्चियों को भी बेचना पड़ रहा है.

देश में दिन–ब–दिन महंगाई बढ़ रही है. इन कृषि कानूनों के चलते अब महंगाई और बढ़ने वाली है. महंगाई का अधिकतर मार भी महिलाओं को ही खाना पड़ता है. बढ़ती महंगाई के चलते क्या खरीदना है? क्या पकाना है? बाल–बच्चों को क्या खिलाना है? आम महिलाएं हर वक्त इन सवालों के घेरे में रहती हैं. बचे–खुचे खाने की वजह से अधिकतर महिलाएं और बालिकाएं कुपोषण से पीड़ित होती हैं.

इसलिए आज किसानों द्वारा जो संघर्ष जारी हैं उनसे महिलाओं को ज्यादा ही लेनादेना है. इसलिए महिला किसानों, महिला खेत मजदूरों, औद्योगिक क्षेत्र की श्रमिक महिलाओं, महिला कर्मचारियों, महिला छोटी व्यापारियों और गृहिणियों आदि सभी उत्पीड़ित महिलाओं से हमारी अपील है कि किसानों द्वारा जारी इन आंदोलनों में वे बढ़चढ़ कर हिस्सा लें. किसान भाईयों के साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ें. 1 फरवरी को किसानों द्वारा आयोजित होने वाले संसद के घेराव कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर हिस्सा लें. 1910 के बस्तर महान भूमकाल की लड़ाकू विरासत को अपनाते हुए उसकी 111वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगामी 10 फरवरी को किसान आंदोलन को जीत के मुकाम तक पहुंचाने के संकल्प दिवस मनाने क्रांतिकारी जनताना सरकार देश के संघर्षरत किसानों सहित तमाम किसानों का आह्वान करती है. इसमें बड़े पैमाने पर भाग लेने महिलाओं को हम अह्वान करते हैं.

क्रांतिकारी अभिवादन के साथ

रनिता

(रनिता हिचामी)

अध्यक्षा

क्रांतिकारी आदिवासी महिला संगठन

दण्डकारण्य